(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SHRI AJAY MAROO (Jharkhand): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Eleventh Report of the Committee on Public Undertakings (Fourteenth Lok Sabha) on "Health Insurance - A Horizontal Study".

ANNOUNCEMENT BY CHAIR

Wireless Fidelity Internet Access Points in Parliament House

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Honourable Members, ...*(Interruptions)*... Order please. I request Members to please maintain order.

Honourable Members, I wish to inform you that the Committee on Provision of Computers to Members of Rajya Sabha has taken the initiative to make the area around Rajya Sabha sector in the Parliament House building wi-fi enabled. This area would include the Outer and Inner Lobbies and the Notice Office of Rajya Sabha. This facility provides Wireless Fidelity Internet access points, which would enable Members to access internet on their laptops etc., without connecting the equipment to any cable or having a connection from an internet service provider. I thank the Chairman and Members of the Committee and the National Informatics Centre for their efforts.

Through this announcement, I also inaugurate the facility. The demonstration of this facility will be intimated to hon. Members.

THE BUDGET (RAILWAYS), 2006-2007 - *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Railway Budget.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैंने आज्ञा मांगी थी, अनुमति मांगी थी कि जो भयंकर ओलावृष्टि राजस्थान में हुई है...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह डिसीज़न हुआ है कि ज़ीरो ऑवर नहीं लेंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने रेलवे के आगामी 2006 साल के लिए लेखा अनुदान 2005-06 की पूरक मांगों और वर्ष 2003-04 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा एवं उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। महोदय, लगभग 40 माननीय सदस्यों ने रेल बजट पर काफी रचनात्मक सुझाव दिए हैं और अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। महोदय, बिना यात्री किराया बढ़ाए, बिना मालगाड़ी का भाड़ा बढ़ाए, रेलवे की रिकॉर्ड वित्तीय उपलब्धि की देश भर में सराहना हुई है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने रेलवे की वित्तीय स्थिति में हुए अभूतपूर्व कायाकल्प का श्रेय अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगति को देने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में यू.पी.ए. सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों एवं लाखों रेलकर्मियों के अथक परिश्रम की बदौलत ही इसे अंजाम दिया गया है। यह सही है कि अर्थ-व्यवस्था में हो रही प्रगति से यातायात की मांग बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमने रेलवे की क्षमता को बढ़ाया और सही नीति अपनाकर बाजार में रेलवे की प्रतियोगी धार को पैना बनाया। एन.डी.ए. शासन के दौरान कई वर्षों में रेलवे की प्रगति दर, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से कम रही थी, जबकि पिछले दो वर्षों में भारतीय रेल ने अर्थव्यवस्था की प्रगति दर से अधिक तेजी से माल लदान कर बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

महोदय, आम आदमी को नज़रअंदाज करने की बात वे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने शासन के दौरान साल-दर-साल यात्री किराया बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला। हमारे बजट के केंद्र में आम आदमी है। यह इससे प्रमाणित होता है कि हमने यात्री किराया बढ़ाने के बजाय घटाया है। गरीब और अमीर का फर्क मिटाने और समाज में समरसता घोलने के लिए मैंने पूर्णतः वातानुकूलित "गरीब रथ" चलाने की घोषणा की थी। इस गाड़ी का किराया आम आदमी की पहुंच के अंदर रखा जाएगा। इससे आम आदमी की पूर्णतः वातानुकूलित गाड़ी में सफर करने की तमन्ना पूरी हो सकेगी। अभी चार "गरीब रथ" सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इस पायलट सेवा के सफल होने पर सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक पूर्णतः वातानुकूलित "गरीब रथ" सेवा शुरू की जाएगी।

गत वर्षों में रेलवे के पास पर्याप्त ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होने एवं डी.आर.एफ. में पर्याप्त प्रावधान नहीं करने के कारण गतायु ट्रैक, सिगनल इत्यादि को समय पर बदलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए सरकार को 17 हज़ार करोड़ रुपए की विशेष रेल संरक्षा निधि का गठन करना पड़ा था। जैसा मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि अब हम डी.आर.एफ. में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अब रेलवे को संरक्षा कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होगी। ट्रैक एवं पुलों को मजबूत करने के लिए रेलवे प्रति वर्ष तीन-चार हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। फलस्वरूप अधिकांश व्यस्त मार्गों पर हल्की रेल को भारी रेल में बदला जा चुका है और हमारी ट्रैक संरचना पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुदृढ़ हुई है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर एवं सभी तकनीकी पहलुओं की जांच-पड़ताल के बाद ही लदान क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। वैगनों के टर्न राउंड टाइम को घटाने एवं माल

लदान क्षमता में प्रति वैगन चार टन की वृद्धि करने से हमारी माल लदान क्षमता में 100 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है। यही रेलवे के वित्तीय कायाकल्प की नींव का पत्थर है।

महोदय, यह आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है कि बजट में कोई विज़न नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि इस बजट को रेलवे के दूरगामी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक ही लाइन पर मालगाड़ी और यात्री गाड़ी चलने का प्रतिकूल असर गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ता है। इस समस्या के निराकरण एवं परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ही मैंने अपने बजट भाषण में 22 हज़ार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पश्चिमी और पूर्वी मार्गों पर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। वामपंथी सहयोगियों के विशेष अनुरोध पर कोलकाता के निकट अवस्थित बंदरगाहों की ओर जाने वाले मार्ग को भी पूर्वी कॉरिडोर से जोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसका उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में किया था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा डायमंड हारबर का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है एवं सरकार द्वारा भी कंटेनर एवं पेट्रोलियम पदार्थों से भरे समुद्री जहाजों के लिए उपयुक्त बंदरगाह बनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की "लुक ईस्ट" नीति के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों एवं चीन, जापान इत्यादि के साथ आयात-निर्यात ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। बजट घोषणा के संबंध में वामपंथी सहयोगियों सहित, मैं पूरे सदन को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के हितों, विशेषकर कोलकाता के निकट अवस्थित बंदरगाहों के विकास हेतु जरूरी रेल संरचना एवं फ्रेट कॉरिडोर के विकास हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही बिना विलम्ब के पूरी की जाएंगी। महोदय, रेलवे परियोजनाओं के लिए निधियों के वितरण के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है। रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार के मद्देनजर विकास परियोजना के लिए गत वर्ष की अपेक्षा 70 प्रतिशत अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है। दोहरीकरण और विद्युतीकरण की योजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता राशि का वितरण राज्यों के बीच प्रचलित फारमूले के आधार पर किया है। इस वर्ष दोहरीकरण योजना के लिए पूरी की पूरी राशि की व्यवस्था कैपिटल फंड से की गई है। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि थ्रूपुट संवर्द्धन, यात्री सुविधा जैसे कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी दी जाएगी और साल के दौरान योजना की प्रगति के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अनेक माननीय सदस्यों ने मुम्बई महानगर में और अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने का मुझसे अनुरोध किया है। जनभावनाओं की कद्र करते हुए हमने वर्ष 2006-07 में मुम्बई में लगभग 40 नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराने एवं लगभग 70 नौ डिब्बों वाली सेवाओं को 12 डिब्बों की सेवाओं में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे बोरीवली-विरार सेक्शन सहित समस्त मुंबई उपनगरीय सेवा के दैनिक यात्रियों को लाभ होगा। महोदय, आन्ध्र प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार एवं विकास से संबंधित एक ज्ञापन मुझे दिया है। वर्ष 2006-07 के लिए राज्य का कुल परिव्यय 422 करोड़ रुपए रखा गया है जो गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है। गूटी से रेनीगुंटा के दोहरीकरण के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए इस वर्ष 68 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस योजना के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। जगियापेट से मल्लाचेरुवू एवं विष्णुपुरम से जनपहाड़ तक नई लाइन निर्माण का प्रस्ताव योजना आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। मैंने निर्देश दिया है कि इस योजना की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही अगले एक माह में पूरी की जाए। धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन के लिए भी कार्य की प्रगति के अनुसार अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद श्री अहमद पटेल

की भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकलेश्वर से राजीपीपला आमान परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेज दिया गया है। दरभंगा से कुशेश्वर स्थान तक नई लाइन निर्माण के सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। इस योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा जा रहा है। पनोली रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 50 प्रतिशत राशि उपलबध कराने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इस कार्य को अविलंब स्वीकृत करने का मैंने निर्देश दिया है। कई अन्य सदस्यों ने भी अपने क्षेत्रों में रेल ओवर ब्रिज के निर्माण का अनुरोध किया है। मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संबंधित राज्य सरकार की 50 प्रतिशत राशि के वहन करने की सहमति प्राप्त होने के बाद बिना विलंब के स्वीकृति दी जाएगी। केरल राज्य के सभी सांसदों ने बैंगलोर से त्रिवेंद्रम के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने, कुछ महत्वपूर्ण मांगों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा आमान परिवर्तन की मांग की है। असम राज्य के सांसदों ने भी दुर्लभ छरांबराई ग्राम तक आमान परितर्वन के लिए सर्वे, काटाखाल-भैराबी आमान परिर्वतन के क़ार्य में तेजी लाने और न्यू मैनागुरी-जोगीघोपा नई लाइन के कार्य को तेजी से पूरा करने तथा आसाम में नए स्लीपर फैक्ट्री की स्थापना करने का अनुरोध किया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केरल एवं आसाम के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और सभी उपयुक्त मांगों पर ससमय कार्रवाई की जाएगी। बैंगलोर-सत्यमंगलम नई लाइन वाया कनकपुरा, चामराजनगर एक स्वीकृत परियोजना है। इसमें बैंगलोर से चामराजनगर वाया कनकपुरा का फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है। महोदय, चामराजनगर से सत्यमंगलम के बीच जो जंगल का क्षेत्र है, इसका सर्वे चल रहा है। इसके पूरा होते ही इस लाइन के निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय सांसदों के अनुरोध पर मैंने जेजो से श्री आनंदपुर साहिब वाया गढ़शंकर के बीच नई लाइन का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इससे ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर की नगरी अमृतसर एवं सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब जुड़ जाएंगे। गोपालपुर-रायगढ़ रेल लिंक के निर्माण के लिए सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है।

उपसभापति महोदय, हमारी बगल में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछले बजट में वर्धा-नांदेड़ लाइन सर्वे कराने का अनुरोध किया था। 206 किलोमीटर की इस लाइन के बारे में हम शीघ्र ही प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति लेकर कार्यवाही शुरू करेंगे। माननीय सदस्यों के बहुत से रचनात्मक सुझाव हमारे पास आए हैं। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को अपने संज्ञान में लिया है। तमिलनाडु की माननीय सदस्या श्रीमती इंदिरा जी ने यह आलोचना की कि तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। मैं माननीय इंदिरा जी को बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु और बिहार को ही इस बजट में टारगेट किया गया है। सभी लोगों ने कहा कि सारी योजनाएं बिहार में ही दी जा रही हैं। आपने जो सुझाव दिया है ब्रॉडगेज के लिए, उस पर हम शीघ्र ध्यान देंगे।

महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी का जो सुझाव आया है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के बारे में पत्र लिखकर मैं उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी दे दूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा रेलवे को दिए गए व्यापक समर्थन के लिए मैं उनको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं।

उपसभापति जी, श्री सुरेश पचौरी जी ने भोपाल-होशंगाबाद-इटारसी के लिए जो ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के बारे में कहा है, इसको पूरा किया जाएगा। श्री विलास मुत्तेमवार जी ने नागपुर-पुणे लाइन के बारे में अनुरोध किया है। पहले वहां नागपुर-पुणे एक्सप्रेस चलती थी,

सैकड़ों लोगों ने मिलकर अनुरोध किया है कि इस गाड़ी को चलाया जाए। निश्चित रूप से हम पुनः नागपुर से इस गाड़ी को चलवाएंगे।

उपसभापति जी, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह रेलवे की आगामी वर्ष 2006-07 के लिए लेखानुदान, चालू वर्ष 2005-06 की पूरक मांगों और 2003-04 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को लौटाने के लिए अपनी स्वीकृति दे ...(व्यवधान)...

STATEMENT BY MINISTERS

Final report of Justice U.C. Banerjee Committee on incident of Fire in Sabarmati Express at Godhra Railway Station on 27th February, 2002.

श्री उपसभापति : सुरेन्द्र लाठ जी, आप बैठिए...(व्यवधान)...

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : इसके साथ ही गोधरा के संबंध में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिए...(व्यवधान)... आप बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद : उपसभापति जी, मुझे बयान भी देना है, इसके बाद आपका बजट होगा, एक साथ कर देने से समय बच जाएगा। बयान देने के लिए हमने अनुमति ली है। हमने हाऊस में बयान देने के लिए कहा था। इसलिए इसकी अनुमति ली जा चुकी है।

उपसभापति महोदय, पश्चिम रेलवे के गोधरा स्टेशन के निकट ट्रेन नंबर 9166 अप साबरमती एक्सप्रेस में दिनांक 27.2.2002 को आग लगने की घटना के कारण 59 जानें गईं और 24 घायल हुए एवं रेलवे परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचा। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त के द्वारा वैधानिक जांच नहीं की गई। सच्चाई की तह में जाने, आग लगने की घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने और उससे जुड़े तत्संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए UPA सरकार ने रेल मंत्रालय की दिनांक 4.9.2004 की अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति को अपना कार्य सुचारू रूप से निष्पादित करने में सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से दिनांक 2.12.2005 की अधिसूचना के तहत समिति को जांच आयोग अधियिम 1952 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गईं।

उपसभापति महोदय, उच्च-स्तरीय समिति ने 17.1.2005 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसे मैं संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर चुका हूं। महोदय, उपरोक्त उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 3-3-2006 को ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल) : वे रिपोर्ट नहीं रख सकते ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वे रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं ...(व्यवधान)... नहीं रख रहे हैं ...(व्यवधान)...